"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2020 — ज्येष्ठ 6, शक 1942

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. — विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19" अधिसूचित की गई है, जिसे इस अधिसूचना में आगे नीति कहा गया है ।

2. नीति के खंड 12.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा, नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई है ।

3. नीति के खंड 12.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन एवं संवर्द्धन करता है -

3.1 परिभाषाएं -

3.1.1 राज्य शासन द्वारा, नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई अधिसूचना के खंड क्रमांक 1 (1) में क्रमांक (छ) के पश्चात् (ज) निम्नानुसार जोड़ी जाती है -

(ज) "स्थाई पूंजी निवेश" से आशय और इसमें सम्मिलित है मूर्त संपत्ति में किया गया निवेश जिसमें भवन, प्लांट-मशीनरी, फर्निशिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर, पात्र इकाई द्वारा उत्पादन या सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन की तिथि से है ।

. इसमें सम्मिलित है -

1. **भवन -**

1.1 नवीन भवन का निर्माण

1.2 पूर्व निर्मित भवन का क्रय (भूमि की लागत को छोड़कर)

1.3 पूर्व से अवस्थित भवन के नवीनीकरण/मरम्मत (नवीनीकरण/मरम्मत की लागत लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की

निर्धारित दरों (Schedule of rates) के आधार पर नवीन भवन की लागत से अधिक नहीं होना चाहिए)

2. प्लांट एवं मशीनरी–

2.1 भारतीय लेखा मानकों द्वारा परिभाषित वित्तीय पट्टे।

2.2 कार्यस्थल पर उपलब्ध प्लांट एवं मशीनरी (जिसमें उपकरण, सांचे/नमूने, छापे, मॉड्यूल्स, सर्वर, राऊटर, पॉवर बैकअप, स्पेयर टूल्स, उनके परिवहन,स्थापना व्यय, तथा परिवहन पर भुगतान की गई बीमे की राशि सहित)

2.3 फर्म द्वारा स्वयं के नाम पर क्रय किये गये वाहन, जिसमें स्थायी पूंजी निवेश की गणना करने पर, कुल स्थायी पूंजी निवेश का दस प्रतिशत, अधिकतम रु. 50.00 लाख सम्मिलित किया जाएगा।

2.4 वाणिज्यिक संचालन के लिए आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, वाणिज्यिक ऑफ द शेल्फ लाईसेंस/सॉफ्टवेयर की लागत, उनकी स्थापना पर किया गया व्यय। इसमें नवीनीकरण एवं संधारण व्यय सम्मिलित नहीं है।

3 इसमें सम्मिलित नहीं है–

3.1 वे निवेश प्रस्ताव जो सामान्य आवेदन पत्र या सैद्धांतिक अनुमोदन में स्वीकृत मात्रा से अधिक के हैं।

3.2 कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और अन्य कंज्यूमेबल्स।

3.3 भुगतान के समर्थन में अग्रिम भुगतान।

3.4 अमूर्त संपत्ति जैसे ब्रांड मूल्यांकन, ट्रेडमार्क आदि (ब्रांड की पहचान स्थापित करने पर किये गये व्यय, ब्रांडिंग, और विपणन के लिए किये गये व्यय व अमूर्त संपत्ति पर व्यय)

3.5 स्वयं या व्यवसायिक उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर के विकास की लागत।

3.6 तकनीकी परामर्श/व्यवहार्यता अध्ययन पर किया गया व्यय।

3.2 "छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014–19" के अंतर्गत प्रोत्साहन/छूट/अनुदान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए संचालन/क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश और प्रक्रिया–

3.2.1 राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–12/2014/56/इ.सू.प्रौ/ दिनांक 31 अगस्त, 2017 एवं एफ 4–45/2015/56/इ.सू.प्रौ/दिनांक 20 जुलाई, 2018 द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान, नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई अधिसूचना के खंड क्रमांक 7 के क्रमांक 7.4 के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती है–

क्रं.	प्रोत्साहन /लाभ का नाम	प्रोत्साहन/ लाभ का विवरण	पात्रता/ शर्तें/अपवाद	**परिचालन दिशा–निर्देश**
7.4	**लीज/ किराये में छूट**	**केवल लीज के लिए –** अधिकतम 25 प्रतिशत का आईटी अधिसूचित क्षेत्र में अनुदान रु. 800.00 प्रति वर्गफीट सीमा तक।	पूर्व से परिभाषित	1. चिप्स आवेदक को सैद्वांतिक अनुमोदन जारी करते समय, स्वीकृत लीज क्षेत्र की अधिकतम सीमा सूचित करेगा। यह एक बार और अंतिम अनुमोदन होगा। 2. निवेशक लीज प्रदान करने वाली इकाई/संस्था को कुल लीज लागत का भुगतान करेगा और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से प्रोत्साहन खंड के तहत पट्टे/किराये की जगह पर छूट के लिए आवेदन करेगा। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ समर्थित होना चाहिए 2.1. पट्टा अनुबंध की प्रति 2.2. भुगतान का प्रमाण पत्र 3. चिप्स आवेदनों की जाँच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 4. लीज लागत पर स्वीकृत छूट को चिप्स/नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित विभाग/प्राधिकरण के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

3.2.2 राज्य शासन द्वारा, नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई अधिसूचना के खंड क्रमांक 7 के क्रमांक 7.7 के कॉलम 5 के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ी जाती है–

क्रं.	प्रोत्साहन /लाभ का नाम	प्रोत्साहन /लाभ का विवरण	पात्रता/शर्तें /अपवाद	**परिचालन दिशा–निर्देश**
7.7	**स्थाई पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन**		पूर्व से परिभाषित	**स्थाई पूंजी निवेश प्रोत्साहन संवितरण के लिए भौतिक सत्यापन प्रक्रिया इस प्रकार होगी–** 1. चिप्स और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन– स्थाई पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने के पूर्व किया जाएगा। 2. निवेशकों द्वारा स्थाई पूंजी निवेश अनुदान के आवेदन पत्र में उल्लिखित संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 3. यह सत्यापन चिप्स और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र

				के संयुक्त दल द्वारा किया जाएगा। इस दल में दोनों संस्थानों के प्रमुख आपने–अपने प्रतिनिधि लिखित रुप में नामांकित करेंगे। जिसकी सूचना निवेशक को दी जाएगी।

भौतिक सत्यापन टीम

सदस्य / अधिकारी	कार्य
नोडल अधिकारी, निवेश संवर्धन, चिप्स	इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस कार्यक्षेत्र के लिए मापदंडों के आधार पर क्रय एवं स्थापित प्लांट और मशीनरी का भौतिक सत्यापन और लागत का सत्यापन।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा नामित सदस्य	
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा नामित सदस्य	भवन, निर्माण और विद्युत कार्य की लोक निर्माण विभाग की एस.ओ.आर. के मापदंडों के आधार पर लागत का अनुमान और भौतिक सत्यापन।
मूल्यांकन एजेंसी / चिप्स द्वारा नामित सदस्य	भौतिक उपस्थिति और निवेशक द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर उसका लेखांकन करना।

4. भौतिक सत्यापन का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा –

- बुनियादी अधोसंरचना का भौतिक सत्यापन
- आईटी / आईटीईएस / ईएसडीएम से संबंधित हार्डवेयर और अन्य उपकरणों का सत्यापन
- उत्पादन के उद्देश्य से निवेशक द्वारा क्रय और स्थापित किये गये पूंजी उपकरण, संयंत्र और मशीनरी का सत्यापन

5. यह सत्यापन निर्धारित प्रारुप में किया जाएगा, जो **परिशिष्ट– "A"** में है।

3.2.3 राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–12 / 2014 / 56 / इ.सू.प्रौ / दिनांक 31 अगस्त, 2017 एवं एफ 4–45 / 2015 / 56 / इ.सू.प्रौ / दिनांक 20 जुलाई, 2018द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान, नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई अधिसूचना के खंड क्रमांक 7 के क्रमांक 7.16 के पश्चात निम्नलिखित नवीन खंड जोड़े जाते हैं–

क्रं.	प्रोत्साहन / लाभ का नाम	प्रोत्साहन / लाभ का विवरण	पात्रता / शर्तें / अपवाद	**परिचालन दिशा–निर्देश**
7.17	इकाईयों को किराये और भूमि	भूमि प्रीमियम पर 80 प्रतिशत छूट और किराये की प्रति वर्ष लागत पर 50 प्रतिशत	इकाई को उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष तक या	1 केवल उन निवेशकों के लिए जिन्होंने आईटी अधिसूचित क्षेत्र में भूमि का अनुरोध किया है और किराये के परिसर के माध्यम से शीघ्र वाणिज्यिक

	प्रीमियम दोनों पर प्रोत्साहन	प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा– 0–10,000 वर्गफीट तक– रु.10 लाख 10,001– 30,000 वर्गफीट तक– रु. 20 लाख 30,000 वर्गफीट से अधिक– रु. 30 लाख	आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की सीमा में प्रोत्साहन देय होगा।	संचालन/उत्पादन प्रारम्भ करने के इच्छुक हैं। 2 यूनिट/उद्यम जो पहले ही (पूर्व में) भूमि प्रीमियम पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर चुके है, वे लीज/किराये की जगह पर छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।
7.18	विद्युत् बिलों के भुगतान पर अनुदान	राज्य में स्थापित डेटा सेंटरों, ई.एस.डी.एम कंपनियों एवं क्लाऊड सेवा प्रदाता इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक स्वयं हेतु उपभुक्त विद्युत यूनिटों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत अनुदान की प्रतिपूर्ति, अधिकतम रु. 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक।	पूर्व से परिभाषित	1 पात्र कंपनी/इकाई चिप्स को त्रैमासिक आधार पर बिजली अनुदान के लिए आवेदन करेगी। 2 किसी तिमाही के लिए बिजली अनुदान का लाभ उठाने के लिए, कंपनी/इकाई को उस तिमाही के तुरंत बाद अगले महीने की 1 और 10 तारीख के दौरान आवेदन करना होगा। 3 आवेदन निम्नलिखित जानकारी के साथ समर्थित होना चाहिए– 3.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को संबोधित बिजली बिलों के 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति/ समायोजन के लिए एक अनुरोध पत्र 3.2 भुगतान के मूल प्रमाणपत्र/ रसीद के साथ बिजली के बिलों की प्रमाणित प्रति 3.3 यूनिट के नाम पर बिजली कनेक्शन होने पर सीएसपीडीसीएल के साथ अनुबंध की प्रति 3.4 यदि बिजली कनेक्शन यूनिट के नाम पर नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी • कनेक्शन और बीपी नंबर के उपयोगकर्ता को वर्णित करते हुए मूल कनेक्शन धारक से हलफनामा • परिसर के लिए कनेक्शन धारक के साथ रेंटल एग्रीमेंट /लीज डीड 4 चिप्स आवेदनों की जाँच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 5 जाँच एवं स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।

7.19	बाजार विकास हेतु सहयोग	**(अ)** राज्य में स्थापित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई द्वारा भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने पर निम्नांकित सहायता दी जाएगी– (1) इकाई द्वारा मेले में भाग लेने पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख की प्रतिपूर्ति। (2) किसी भी इकाई को यह सहयोग एक बार ही दिया जाएगा। **(ब)** भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के छत्तीसगढ़ मंडप में भागीदारी हेतु उद्योग संघों/समूहों को निम्नांकित सहायता दी जाएगी– (1) भागीदारी पर व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख की प्रतिपूर्ति। (2) न्यूनतम 5 इकाईयों को समूह का हिस्सा होना चाहिए।	पूर्व से परिभाषित	1 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई (एमएसएमई) इकाई /उद्योग निकाय, पत्र द्वारा चिप्स को आयोजन से कम से कम 45 दिनों पहले उनकी भागीदारी के बारे में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। पत्र के साथ निम्न अभिलेख होना चाहिए– 1.1 एमएसएमई के लिए – • एमएसएमई सहभागिता का औचित्य/कारण और आवश्यक राशि का विवरण • इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट • राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया प्रासंगिक पंजीकरण प्रमाण पत्र • पिछले 3 वर्षों में किये गये ऑडिट का वित्तीय विवरण 1.2 उद्योग निकाय के लिए • सहभागिता का औचित्य/कारण और आवश्यक राशि का विवरण • भारत /राज्य सरकार सरकार के साथ वैधानिक पंजीकरण का प्रमाण • नाम, प्रोफाइल, इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट और न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय विवरण (अंतिम 2 वित्तीय वर्ष) जो समूह का हिस्सा होगा। • पिछले 3 वर्षों में उद्योग निकाय का ऑडिट किया गया वित्तीय विवरण 2 चिप्स आवेदनों की जाँच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स अनुमोदन प्राधिकारी होंगे तथा चिप्स का निर्णय अंतिम होगा। 3 उक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी के बाद, एमएसएमई इकाई /उद्योग निकाय, भागीदारी के 1 महिने के भीतर चिप्स में व्यय का प्रमाण प्रस्तुत

				करेगा। आवेदन में शामिल होंगे • बिलों की प्रति • विधेयकों का प्रमाण 4 चिप्स दावों से संबंधित तथ्यों की सत्यता के बारे में व्यय के प्रमाण की जांच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 5 चिप्स अनुमोदित राशि को लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में हस्तांतरित करेगा।
7.20	बैंडविड्थ चार्जेज, पी. आर. आई एवं लीज लाइन पर प्रोत्साहन	डेटा सेंटर एवं क्लाऊड सर्विस प्रोवाईडर इकाई को छोड़ कर अन्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की राज्य में स्थापित इकाइयों द्वारा बैंडविड्थ चार्जेस, पी. आर.आई एवं लीज लाइन पर किये गये भुगतान की 10 प्रतिशत, अधिकतम रु. 25 लाख (रु. पच्चीस लाख) प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति, उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष तक की जाए।	पूर्व से परिभाषित	1 पात्र इकाई वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोत्साहन के लिए आवेदन करेगी। 2 योजना के तहत पात्र इकाई/उद्यम निम्नलिखित सूचना के साथ निर्धारित प्रारूप में चिप्स को आवेदन प्रस्तुत करेगाः 2.1 यूनिट/इकाई द्वारा उपयोग की गयी कुल बैंडविड्थ और प्राइमरी रेट इंटरफेस (पी.आर.आई) और लीज लाइन सेवाओं की रिपोर्ट। 2.2 बैंडविड्थ शुल्कों के लिए किए गए सभी बिलों और भुगतानों की प्रति। 3 चिप्स आवेदनों की जाँच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 4 जाँच एवं स्वीकृति के पश्चात हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में स्वीकृत राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
7.21	परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति	नया रायपुर में स्थापित इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 2 वर्ष तक भुगतान किये गए वास्तविक परिवहन व्यय में 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।	पूर्व से परिभाषित	1 परिवहन लागत की गणना रायपुर और/तथा नया रायपुर के लिए कर्मचारियों हेतु लागू प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर के आधार पर की जाएगी। 2. परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु. 25 लाख प्रति वर्ष होगी। 3 पात्र इकाई वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोत्साहन के लिए आवेदन करेगा। 4 योजना के तहत पात्र इकाई/उद्यम निम्नलिखित सूचना के साथ निर्धारित प्रारूप में चिप्स को आवेदन प्रस्तुत करेगा– 4.1 तृतीय–पक्ष एजेंसी/विक्रेता के माध्यम से प्राप्त परिवहन सेवाओं के लिए– ▪ सी.ई.ओ., चिप्स को संबोधित परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध

				पत्र। ▪ तृतीय पक्ष एजेंसी/विक्रेता के साथ अनुबंध की प्रति। ▪ अनुमोदित यात्रा कि.मी. लॉग की प्रतिलिपि। 4.2 कंपनी के स्वयं के वाहनों के माध्यम से परिवहन सेवाओं के लिए– • अनुमोदित यात्रा कि.मी. लॉग की प्रतिलिपि। 5 चिप्स आवेदनों की जाँच करेगा और आवश्यकता होने पर कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करेगा। 6 जाँच एवं स्वीकृति के पश्चात हितग्राही के पंजीकृत बैंक खाते में स्वीकृत राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
7.22	अनुसंधान एवं विकास के लिये औद्योगिक इकाई एवं अकादमिक संस्थान की सहभागिता पर अनुदान	**(1) स्टार्ट अप एवं सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाई हेतु**– प्रथम दो वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर इकाई द्वारा व्यय की गई राशि की दो–तिहाई राशि, अधिकतम रु. एक करोड़ तक, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। **(2) बड़े उद्यमियों हेतु**– प्रथम दो वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर इकाई द्वारा व्यय की गई राशि की आधी राशि, अधिकतम रु. 1 करोड़ तक, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान परियोजनाओं की आवश्यक शर्तें**– (अ) शैक्षणिक संस्थान में परियोजना अन्वेषक (प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर) होना चाहिए तथा कम से कम दो वर्ष के लिए बैचलर कार्यक्रम संचालित करने का अनुभव होना चाहिए। (ब) इकाई के अनुसंधान एवं विकास कार्य में राज्य के लिये मूल्य संवर्द्धन आऊटपुट होना चाहिए।	1 पात्र स्टार्ट अप एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी इकाईया तथा बड़े उद्यमी निर्धारित प्रारूप में चिप्स को आवेदन और परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ समर्थित होगा। 1.1 इसका प्रमाण कि शैक्षणिक संस्थान में स्नातक कार्यक्रम कम से कम 2 वर्षों से चल रहा है। अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का समर्थन केवल छत्तीसगढ़ स्थित सरकारी शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग के लिए लागू होगा। 1.2 स्व–घोषणा की परियोजना का कार्यकाल 2 वर्ष तक होगा और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए स्वीकृत कार्यकाल की समय सीमा का पालन न करने पर समर्थन रद्द माना जाएगा। 2 आवेदन और प्रस्तावित परियोजना का चिप्स द्वारा गठित परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी.आर.एस.जी) द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा निमंत्रण समय सीमा चिप्स द्वारा विस्तारित किया जाएगा। किसी भी आमंत्रित सदस्य के 'कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' की दशा पर, कथित सदस्य पीआरएसजी बैठक का भाग नहीं होंगे।

				3 चिप्स अनुमोदन प्राधिकारी होगा तथा चिप्स का निर्णय अंतिम होगा 4 चरणबद्ध अनुदान संवितरण और संबंधित प्रक्रियाएँ 'टी सी–गवर्निंग–सब्सिडी' दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगी।
7.23	सभी प्रोत्साहन हेतु योग्यता पर परिचालन –	भूमि के प्रीमियम पर छूट तथा स्टॉम्प ड्यूटी में छूट के अतिरिक्त सभी प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन प्रारम्भ करने की तारीख से प्रदान किये जायेंगे।	–	भूमि के प्रीमियम पर छूट तथा स्टॉम्प ड्यूटी में छूट,के अतिरिक्त सभी प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन प्रारम्भ करने की तारीख या सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से, जो भी बाद में हो, प्रदान किये जायेंगे। भूमि के प्रीमियम पर छूट तथा स्टॉम्प ड्यूटी में छूट सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख के बाद प्रदान किय जाएंगें।

3.3. राज्य शासन द्वारा नीति के अंतर्गत पात्र इकाईयों को लाभ, प्रोत्साहन एवं अनुदान स्वीकृत करने हेतु एकल खिड़की समाशोधन के लिए दिनांक 27 जनवरी, 2016 को जारी की गई अधिसूचना के खंड 8 के पश्चात खंड 8 (अ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है–

8 (अ) बीजक (इन्वाईस), भुगतान के प्रकार और संबंधित पक्षों के लेन–देन पर सामान्य दिशानिर्देश–

1 अनुदान/ प्रोत्साहन या छूट प्रदान करने के लिए कर सम्मिलित बीजक ही स्वीकार्य होंगे, जो इकाई के नाम पर होना अनिवार्य होगा।

2 नकद में भुगतान किए गए कर सम्मिलित बीजक पर विचार नहीं किया जाएगा।

3 वैध कर सम्मिलित चालान के अतिरिक्त किसी भी खर्च/बीजक पर विचार नहीं किया जाएगा – बीजक पर वैट/टिन/सीएसटी/जीएसटी विवरण आदि प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। यदि वैट/टीन/सीएसटी/ जीएसटी विवरण, टर्न ओवर सीमा से नीचे के कारोबार होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे मामलों में दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम (गुमास्ता) के तहत व्यापार लाइसेंस पर विचार किया जा सकता है। जिसकी जानकारी बीजक पर होना आवश्यक है।

4 कर सम्मिलित चालान कंप्यूटर जनरेट या हस्तलिखित हो सकते है, परन्तु उन पर उचित विक्रेता या सेवा प्रदाता की कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर और तारीख होना अनिवार्य होगा।

5 चेक/डिमांड ड्राफ्ट /डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड /एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आईएमपीएस /यूपीआई/वॉलेट के माध्यम से किये गये बीजक भुगतान प्रोत्साहन के अंतर्गत पूरी राशि की अर्हता प्राप्त करने पर विचार हेतु योग्य हैं। ऐसे मामलों में, लेन–देन के प्रमाण /कथन समर्थित दस्तावेज प्रदान करना अनिवार्य होगा।

6 किसी भी प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रस्तुत बीजक पर निम्नलिखित विक्रेता या सेवा प्रदाता नहीं हो सकता है–

अ. कोई पूर्व या वर्तमान निदेशक

ब. कोई पूर्व या वर्तमान शेयरधारक

स. किसी भी पूर्व या वर्तमान निदेशक या संबंधित पार्टी के शेयरधारक के रिश्तेदार, जिसमें सम्मिलित हैं–

1 एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य या

2 पति /पत्नी या

3 भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 एवं आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई सूची के अनुसार संबंधी।

4. इस संबंध में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2016 की अन्य कंडिकाएं/ खंड अपरिवर्तित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्नोई, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 20 मई 2020

क्रमांक-एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ., दिनांक 20-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्नोई, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 20th May 2020

NOTIFICATION

No. F 4-12/2014/56/EIT.— As per department notification number F 4-12/2014/56/EIT dated 25 February 2015 "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019" has been notified, herein after referred as the 'Policy' .

2. In exercise of the powers conferred by sub clause (2) of clause 12 of the policy, the State Government has made operational guidelines for Single Window Clearance system, approvals and Incentives/Benefits to the eligible Electronics, IT & ITeS industry /companies which was released by the department notification dated 27 January 2016.

3. In exercise of the powers conferred by sub clause (2) of clause 12 of the policy, the State Government, hereby, makes the following amendments and additions in operational guidelines released through notification dated 27 January 2016 for Single Window Clearance system, approvals and Incentives/Benefits to the eligible Electronics, IT & ITeS industry /companies, namely –

3.1 Definitions –

3.1.1 In the State Government approved operational guidelines for Single Window Clearance system, approvals and Incentives/Benefits to the eligible Electronics, IT & ITeS industry /companies which was released by the department notification dated 27 January 2016, after clause 1.1, number 'g)', the following shall be inserted, namely –

h) "**Fixed Capital Investment**" means the investment made in tangible assets which are required building, plant, machinery, furnishing, hardware and software assets, excluding the cost of the land, required to produce products or services by eligible unit, till the date of commencement of commercial operation/production.

- This Includes –

1. Building

1.1 Construction of new building

1.2 Purchase of the previously existing building (excluding cost of the land)

1.3 Renovation/repair of the previously existing building (Renovation/ repair cost should not exceed the cost of creating the new building (reference- Schedule of Rates S.O.R)).

2. Plant and Machinery

2.1 Only financial lease will be considered as defined by Indian Accounting Standards.

2.2 Cost of plant and machinery onsite (including the cost of equipment such as tools, jigs, dies, moulds, computers, servers, routers, power backups and spare tools, their transportation, installation charges and transit insurance premium).

2.3 Vehicles purchased in the firm's name, up to 10% of total Fixed Capital Investment (FCI), maximum Rs. 50 lakhs will be considered for FCI subsidy calculation.

2.4 Purchase cost of commercial off-the-shelf software(s) required for commercial operation like operating systems, antivirus and licences inclusive of the cost incurred in their installation and exclusive of their renewal and/or maintenance costs.

3. This does not include –

3.1 Investment which has been in excess of investment quantum specified in Common Application Form (CAF) and/or approved under In-principal approval.

3.2 Working capital, raw material, stores and other consumables.

3.3 Advances, expenses not supported by payment proof.

3.4 Intangible assets like brand valuation, trademarks etc. (Expenses incurred towards creation of brand identity elements and any expenses incurred towards branding and marketing; Expenses done on intangible assets).

3.5 Cost of development of software(s) for self or commercial use.

3.6 Expenditure on Technical Consultancy / Feasibility study.

3.2 Operational / implementation guidelines and procedures to avail incentives / rebates / grants and other benefits under "Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019"

3.2.1 To approve below mentioned benefits, incentives and grants notified by the State Government notification number F 4-12/ 2014/56/EIT dated 31 August 2017 and F 4-45/2015/56/EIT dated 20 July 2018 to eligible units, in the State Government approved operational guidelines released by the department notification dated 27 January 2016, at end of clause 7, entry 7.4, the following shall be added, namely –

S. No.	Incentive Head	Approved Incentive	Eligibility Criteria	Operational Guideline
7.4	Rebate on Lease/Rental space	Units established in the state will be eligible for 25% subsidy on lease costs, with upper limit of Rs. 800 per sqf. in an IT notified area		1. While issuing In-Principle Approval to the applicant, CHiPS will communicate upper limit of approved lease space. This will be a one-time and final approval. 2. Investor will pay total lease cost to issuing entity and apply for "Rebate on Lease/Rental Space" under "Incentives" section through single window clearance system. The application should be supported with following documents: 2.1 Copy of lease agreement 2.2 Proof of payment. 3. CHiPS will scrutinize the application and may seek any other information as required. 4. The approved rebate on lease cost will be transferred by CHiPS/Nodal Agency to the bank account of concerned department/authority.

3.2.2 To approve benefits, incentives and grants to eligible units, in the State Government approved operational guidelines released by the department notification dated 27 January 2016, at end of clause 7, entry 7.7, column 5, the following shall be added, namely –

S. No.	Incentive Head	Approved Incentive	Eligibility Criteria	Operational Guideline
7.7	Incentive for Fixed Capital Investment			**The physical verification process for disbursement of fixed capital investment incentives will be as follows –** 1. Joint physical verification by CHiPS and District Industries Centre will be done prior to disbursement of Fixed investment incentives. 2. Physical verification will be done of assets mentioned in

				the Fixed Capital Investment application by the investors. 3. This verification will be done by a joint team of CHiPS and District Industries Centre. Chief/Head of both the institutions will nominate their representatives in writing to be part of Joint Physical verification team. This information will be shared with the investor.

Physical Verification Team

Member/Officer	Task
Nodal Officer, Investment, CHiPS	Physical presence and cost estimation based on parameters for Plant and Machinery-Electronics, IT & ITeS aspect
Member assigned by CEO CHiPS	
Member assigned by DIC/CSIDC	Physical presence and cost estimation based on parameters for building & construction and electrical aspect
Member assigned by Appraisal Agency/ Finance Department, CHiPS	Physical presence and its alignment with available financial records for financial aspect

4. The scope of Joint Physical Verification would entail:
- Verification of physical infrastructure
- Verification of IT/ITeS/ESDM related hardware and other equipment
- Verification of any other capital equipment, plant or machinery claimed to be

				procured and installed by the investor for purposes of production 5. This verification will be done in the prescribed format, as per Appendix **"A".**

3.2.3 To approve below mentioned benefits, incentives and grants notified by the State Government notification number F 4-12/ 2014/56/EIT dated 31 August 2017 and F 4-45/2015/56/EIT dated 20 July 2018 to eligible units, in the State Government approved operational guidelines released by the department notification dated 27 January 2016, after clause 7, entry 7.16, the following new entries shall be inserted, namely –

S. No.	Incentive Head	Approved Incentive	Eligibility Criteria	Operational Guideline
7.17	Subsidy on both rental and land Premium	80% rebate on land premium AND 50% reimbursement on rental cost per annum Max limit - 0 -10,000 sqf – Rs 10 lakh 10,001 – 30,000 sqf – Rs. 20 lakh 30,000 sqf above - Rs. 30 lakh	Incentive to unit for the period of three years from the date of commencement of production or till the completion of construction work on the allotted land, whichever is earlier.	1. Only for investors who have requested land at IT notified area and intends to start commercial operations at the earliest through rental premises. 2. The unit/enterprise which has already (in the past) claimed for Land premium subsidy are not eligible for Rebate on Lease/Rental space.
7.18	Power Tariff Subsidy	Units established in the state, that are either Data Center, Cloud Service Provider or ESDM units will be eligible for 10% power tariff subsidy through reimbursement with an upper limit of Rs 1.5 crore per		1. The eligible company/unit will apply for power subsidy on a quarterly basis to CHiPS. 2. To avail power subsidy for a particular quarter, the company/unit must apply during the 1st and 10th dates of the immediate next month following that quarter. 3. Application should be supported with following information: 3.1 A request letter for reimbursement/adjustment of

		annum, for a period of 5 years from start of commercial production.		the 10% of electricity bills addressed to CEO, CHiPS 3.2 Copy of the electricity bills with payment proof 3.3 Copy of agreement with CSPDCL if electricity connection is in the name of the unit 3.4 If electricity connection is not in the name of the unit, then following documents will be required: • An affidavit from original connection holder stating the user of the connection and BP number • Rental agreement /Lease deed with the connection holder for the premises 4. CHiPS will scrutinize the application and may seek any other information as required. 5. The approved subsidy amount will be transferred by CHiPS to the registered bank account of beneficiary.
7.19	Market Development Support	A. Assistance to MSME units for participating in international Trade Fairs outside India. 1. 50% support for participation not exceeding Rs. 5 lakhs per such visit outside India. 2. One unit can avail this support only once. B. Assistance to Industry Bodies for participating		1. The Micro Small and Medium Enterprise (MSME) unit/Industry body will submit a letter informing CHiPS of their participation at least 45 calendar days prior to the event. The letter should be supported with: 1.1 For MSME – a. Reason for participation and quantum of support required. b. Certificate of Incorporation c. Relevant registration certificate issued by State Govt. d. Last 3 years audited financial statements 1.2 For Industry Body – a. Reason for participation and quantum of support required b. Proof of legal registration with Govt. of India/State Government

		in international Trade Fairs outside India as Chhattisgarh Pavilion. 1. 50% support for participation not exceeding Rs 10 lakhs per such visit outside India. 2. Minimum 5 industrial units should be part of the group.		c. Name, profiles, certificates of incorporation and audited financial statements (last 2 financial years) of at least 5 industrial units that will be a part of the group d. Last 3 years audited financial statements of industry body 2. CHiPS will review the application and may seek any other information as required CEO, CHiPS will be the final approving authority. 3. Post participation in the said International Trade Fair, the MSME unit/Industry body will submit proof of expense to CHIPS within 1 month of participation. The application will include: a. Copy of the Bills b. Proof of Bills paid. 4. CHiPS will scrutinize the proof of expense regarding veracity of facts concerned to the claims and may seek any other information as required. 5. CHiPS will transfer approved amount to the registered bank account of beneficiary.
7.20	Subsidy on Bandwidth, PRI and Leaseline Charges	IT & ITeS Units established in the State, excluding Data Center and cloud service providers, will be entitled for subsidy through reimbursement of 10% of the total charges paid towards availing internet bandwidth from ISP, PRI and leased line		1. The eligible unit shall apply for incentives at the end of financial year. 2. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information: 2.1 Report on total bandwidth and Primary Rate Interface (PRI) & Lease Line services used by the unit/enterprise. 2.2 Copy of all bills and payments made towards bandwidth charges.

		charge with a maximum limit of INR 25 Lakhs per annum for 3 years.		3. CHiPS will scrutinize the applications and may seek any other information as required. 4. Post scrutiny and appraisal, the eligible amount will be paid to the registered bank account of beneficiary.
7.21	Subsidy on Transportation Cost	Units established in Naya Raipur will be eligible for 50% reimbursement on actual expenditure incurred on transportation cost, for a period of 2 years from start of commercial production.		1. The maximum permissible transportation cost per employee per month will be governed by applicable government tariff rates for Raipur and Naya Raipur. 2. The total subsidy on transportation cost will be up to Rs. 25 lakh per year. 3. The eligible unit shall apply for incentives at the end of financial year. 4. The eligible unit/enterprise under the scheme will apply to the CHiPS in the prescribed format along with following information: 4.1 For transport services availed through a third-party agency/vendor: • A request letter for reimbursement of transportation cost addressed to CEO, CHiPS • Copy of contract with third party agency/vendor • Copy of approved travel km log 4.2 For transport services through company owned vehicles: • Copy of approved travel km log 5. CHiPS will scrutinize the applications and may seek any other information as required. 6. Post scrutiny and appraisal, the eligible amount will be paid to the registered bank account of beneficiary.

7.22	Support for Research and Development (R&D)	**1. For Startups and MSMEs** – Incentive will be two-third the quantum of investment by the industry partner in the first 2 years, not exceeding Rs. 1 crore. **2. For Large enterprises** – Incentive will be 50% of the quantum of investment by the industry partner in the first 2 years, not exceeding Rs. 1 crore.	**Essential conditions for Research and Development projects support** – A. Academic institute should be Project Investigator and should have Bachelor's program running for at least 2 years. B. Output of R&D must be used for value addition within the State.	1. The eligible startups & Small and Medium Enterprises (SMEs) / large companies will submit application and project proposal to CHiPS in the prescribed format. The application will be supported with below listed documents: 1.1 Proof that academic institute has Bachelor's program running for at least 2 years. The Support for Research and Development (R&D) is applicable to only to collaborations with Government academic institution(s) based out of Chhattisgarh. 1.2 Self – declaration that project tenure will be up to 2 years and acknowledgment that support for Research and Development (R&D) will stand cancelled if the tenure timelines are breached 2. The application and proposed project will be appraised by Project Review and Steering Group (PRSG) formed by CHiPS. Invited members will have a tenure of 2yrs. Invitation will be extended by Dept. of E&IT/CHiPS. In case of any conflict of interest of any invited member, the PRSG will meet without the member in question. 3. CHiPS will be the final approving authority. 4. The phased subsidy disbursement and associated processes will be governed by terms and conditions specified in **'TC_Governing_Subsidy'** document.

7.23	Guidelines on Eligibility for all Incentives	All incentives disbursement (except 'Subsidy on Land Premium' and 'Stamp Duty Exemption') will be given from the date of start of commercial production.		All incentives disbursement (except 'Subsidy on Land Premium' and 'Stamp Duty Exemption') will be given either from the date of In-Principle Approval or from the date of start of commercial production, whichever is later. 'Subsidy on Land Premium' and 'Stamp Duty Exemption' will be given post date of In-Principle Approval.

3.3 To approve benefits, incentives and grants to eligible units, in the State Government approved operational guidelines released by the department notification dated 27 January 2016, after clause 8, the following clause 8 (A) shall be inserted, namely –

8 (A) General Guidelines on Invoices, Payment Mode and Related Party Transactions –

1. Taxable invoices should only be in the name of the unit under consideration of subsidy.

2. Taxable invoices paid in cash will not be considered.

3. Any expense without valid taxable invoice will not be considered – invoice needs to have VAT/TIN/CST/GST detail. If VAT/TIN/CST/GST details are not available due to turnover below limit, in such cases business license under shops & establishment Act (Gomasta) can be considered.

4. Taxable invoices can either be computer generated or hand written but should have proper company seal and signature of the seller or service provider.

5. Invoices with payment mode as cheque / demand draft / debit card / credit card / NEFT / RTGS / IMPS / UPI / Wallets, qualify for full amount consideration. In such cases, supporting transaction proof/statement are required.

6. The seller or service provider on any invoice for any incentive head, can't be:

   a. Any Past or current director

   b. Any Past or current shareholder

   c. Relative of any past or current director or shareholder of the concerned party. "Relative" includes:
      1. members of a Hindu undivided family; or
      2. husband/wife;
      3. Related party as clarified in Companies Act, 2013 or Income Tax Act, 1961

4. The other clauses/sub-clauses in the notification dated 27 January 2016 released in this regard will remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SAMEER VISHNOI, Joint Secretary.

Appendix A - Physical Verification Report

"Physical Verification Report for Fixed Capital Investment Subsidy"

Inspection/Verification Date - / /

1. Name and address of the unit –

2. Sector of the unit –

ESDM		**IT**		**ITeS**	

3. Place of the established unit –
   - Place –
   - Village –
   - Tehsil –
   - District –

4. Date of commencement of commercial operation –

5. Tip/ Opinion/ Recommendation – On physical infrastructure, hardware and other equipment, based on the inspection report of Annexure A, B and C

Appendix A - Physical Verification Report

6. Other points which might be considered during decision making on claim processing

Recommendation and Opinion

Signature of Chief DIC Officer

(Including date)

Name –

Designation –

Office –

Annexure A

"Physical Verification Report for Fixed Capital Investment Subsidy"

Inspection/Verification Date - / /

1. Name and address of the unit –

2. Sector of the unit –

ESDM		**IT**		**ITeS**	

3. Size of the unit – Micro and Small / Medium / Large

4. Place of the established unit –
   - Place –
   - Village –
   - Tehsil –
   - District –

5. Registration –
   - MSME Registration (if applicable) –
   - Udyog Aadhar Memorandum –
   - GST Registration –
   - Any other certificate issued by authorized officer –

6. Connected electricity load and connection date –

7. Date of commencement of commercial operation –

8. Product and annual production capacity (Volume and value) OR business / types of related services, capacity and usage OR annual installed capacity OR not applicable –

9. Details of fixed capital expenditure –

S. No.	Gross capital expenditure as per project report	Fixed capital investment done till date of commencement of commercial operation (in Rupees)
1.	1.1 Land -	
	Size of the land	

Annexure A

	Actual purchase price / Premium	
	Stamp duty amount	
	Registration amount	
	1.2 Land development -	
Total		
2.	Building	
	2.1 Factory / Unit building	
	2.2 Laboratory building	
	2.3 Research building	
	2.4 Administrative building	
	2.5 Canteen	
	2.6 Labour rest house	
	2.7 Parking	
	2.8 Security post	
	2.9 Warehouses	
	2.10 Others (Provide details)	
Total		
3.	Investment for electricity supply	
	3.1 Payment done to CG State Electricity Board/ Private electricity distribution company (excluding security deposit and past due payments)	
	3.2 Investment done on setup of captive electricity plant	
Total		
4.	Investment for water supply	
	4.1 Investment done on arrangement for required water supply at industry complex for industrial use (excluding security deposit and past due payments)	

10. Fixed capital investment related physical condition –

a. Land (Details of allotted land and land used for industrial use)

b. Land development (Land levelling, deepening and drainage construction)

Annexure A

c. Shed building (Classification of built up space)

d. Investment for electricity supply (Date of electricity connection and other points)

e. Investment for water supply (Date of water connection and other points)

11. Electricity load –

12. Any other physical verification points raised by rating agency for inspection –

13. Tip/ Opinion / Recommendation –

1. Related to investment done on guest house, prayer room, temple, employee residence, residential house, boundary wall, park and land development at the time of physical site inspection

2. Verification of list of investment done as part of fixed capital investment as per financial statements of the unit

3. Tips on reasons of delay by the unit for delayed applications

4. Reason for disqualification of fixed capital investment (Item wise, expense wise)

5. Unambiguous recommendation on eligibility of grant

Annexure A

14. Other points, which can be considered important during subsidy processing

Signature of verifying officer

(Including date)

Name –

Designation –

Office –

Recommendation and opinion of Additional Chief Executive Officer/ Chief Executive Officer on recommendations and opinion of verifying officer

Annexure B

"Physical Verification Report for Fixed Capital Investment Subsidy"

Inspection/Verification Date - / /

1. Name and address of the unit –

2. Sector of the unit –

ESDM		**IT**		**ITeS**	

3. Size of the unit – Micro and Small / Medium / Large

4. Form of industrial unit – New unit/ Expansion of existing unit

5. Place of the established unit –
   - Place –
   - Village –
   - Tehsil –
   - District –

6. Date of commencement of commercial operation –

7. Details of fixed capital investment -

S. No.	Gross capital expenditure as per project report	Fixed capital investment done till date of commencement of commercial operation (in Rupees)
1	IT/ITeS equipment/hardware	
	1.1 Notebook	
	1.2 Tablet computer	
	1.3 Desktop – PC	
	1.4 Servers	
	1.5 Printers	
	1.6 CCTV and security cameras	
	1.7 Photocopiers	
	1.8 Scanners	
	1.9 P C projectors	
	1.10 Biometric authentication device	
	1.11 Air conditioner	
	1.12 TV / Monitors	

Annexure B

	1.13 Leased Line Network equipment	
	1.14 Others (Mention details)	
Total		
2	ESDM equipment/hardware	
	2.1 Mention details	
	2.2	
	2.3	
	2.4	
	2.5	
	2.6	
	2.7	
	2.8	
	2.9	
	2.10	
	2.11	
	2.12	
	2.13	
	2.14	
Total		

Note: If applicant has provided any details in Section 7, subsection 1 or 2, in such cases applicant would have to compulsorily furnish complete details in Section 13 in attached format.

8. Fixed capital investment related physical condition –
    1. ESDM / IT / ITeS equipment/ hardware (installed or not / equipment/hardware working or not)

    2. Requirement of ESDM / IT / ITeS equipment/ hardware established for commercial operation or not

    3. Quantity of ESDM / IT / ITeS equipment/ hardware as per requirement of commercial operation or not

9. Any other physical verification points raised by rating agency for inspection –

10. Points on other units of the firm that have been provided subsidy/concession or rebates (if applicable) –
    1. Name and address
    2. Unit address

Annexure B

a. Village/City
b. Tehsil
c. District

11. Tip/ Opinion / Recommendation –
    1. Verification of list of investment done as part of fixed capital investment as per financial statements of the unit

    2. Points related to eligibility of industry as part of saturated sector/ core sector / priority sector

    3. Reason for disqualification of fixed capital investment (Item wise, expense wise)

    4. Clear ambiguity related to eligibility of grant

12. Other points, which can be considered important during subsidy processing

Annexure B

13. Format – Detailed information of equipment and hardware

S. No.	Make	Model	Serial No	Date of purchase	Status of warranty	Seller	Value	Challan Number	GST Number/ Service Tax Number
1									
2									
3									
4									
5									

Signature of verifying officer

(Including date)

Name –

Designation –

Office –

Recommendation and opinion of Additional Chief Executive Officer/ Chief Executive Officer on recommendations and opinion of verifying officer

Annexure C

"Physical Verification Report for Fixed Capital Investment Subsidy"

Inspection/Verification Date - / /

1. Name and address of the unit –

2. Sector of the unit –

ESDM		**IT**		**ITeS**	

3. Size of the unit – Micro and Small / Medium / Large

4. Form of industrial unit – New unit/ Expansion of existing unit

5. Place of the established unit –
   - Place –
   - Village –
   - Tehsil –
   - District –

6. Date of commencement of commercial operation –

7. Details of fixed capital investment -

S. No.	Gross capital expenditure as per project report	Fixed capital investment done till date of commencement of commercial operation (in Rupees)
1	1.1 Plant and Machinery (including machinery on lease)	
	1.2 Capital Equipment	
	1.3 Pollution control plant, Plant and equipment used in laboratory and research	
	1.4 Testing equipment	
	1.5 Establishment related expenses	

Annexure C

	1.6 Others (provide details)	
Total		

8. Fixed capital investment related physical condition –

   a. Plant and machinery (installed or not / Machinery working or not)

   b. Capital and other equipment (installed or not / equipment working or not)

9. Any other physical verification points raised by rating agency for inspection –

10. Points on other units of the firm that have been provided subsidy/concession or rebates (if applicable) –
    1. Name and address
    2. Unit address
       a. Village/City
       b. Tehsil
       c. District

11. Tip/ Opinion / Recommendation –
    1. Verification of list of investment done as part of fixed capital investment as per financial statements of the unit

    2. Reason for disqualification of fixed capital investment (Item wise, expense wise)

    3. Details of other past subsidy/concession or rebates received from the department

    4. Clear ambiguity related to eligibility of grant

Annexure C

12. Other points, which can be considered important during subsidy processing

Annexure C

13. Format – Detailed information of plant and machinery, capital and other equipment and hardware

S. No.	Make	Model	Serial No	Date of purchase	Status of warranty	Seller	Value	Challan Number	GST Number/ Service Tax Number

Signature of verifying officer

(Including date)

Name –

Designation –

Office –

Recommendation and opinion of Additional Chief Executive Officer/ Chief Executive Officer on recommendations and opinion of verifying officer

"Physical Verification Report for Lease or Rental Subsidy"

Inspection/Verification Date - / /

1. Name and address of the unit –

2. Sector of the unit –

ESDM		**IT**		**ITeS**	

3. Name and address of the land owner (including Village/Tehsil/District)

4. Start date of lease/rent

5. Date of commencement of commercial operation –

6. Lease/Rent related physical condition –
   I. Date, reference number and period of validity of registered lease/rental agreement

   II. Details of the lease/rental space used for commercial operation

   III. Area of the lease/rental space used for commercial operation

   IV. Monthly rental of the lease/rental space used for commercial operation

7. Any other physical verification points raised by rating agency for inspection –

8. Tip/ Opinion / Recommendation –
   1. Points related to guest house, worship place, temple, employee residence, other residential place, boundary wall, park and land development at the time of physical verification

   2. Clear ambiguity related to eligibility of grant

   3. Other points, which can be considered important during subsidy processing

Signature of verifying officer

(Including date)

Name –

Designation –

Office –

Recommendation and opinion of Additional Chief Executive Officer/ Chief Executive Officer on recommendations and opinion of verifying officer

TC_Governing_Subsidy

Chhattisgarh Infotech Promotion Society

Department of Electronics and IT

Government of Chhattisgarh

The grant is for the specific project as approved by Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) and shall be subject to the conditions listed below. **The proposal originating industry and academic institution shall give an undertaking that they agree to be governed by these conditions.**

1. Grant under this scheme will only be released to the participating academic institution.
2. The grant amount shall be i) spent for the project within the specified time; and ii) Any portion of the grant, which is not ultimately required for expenditure for the approved purposes, shall be duly surrendered to CHiPS;
3. The academic institution shall maintain an audited record in the form of a register in the prescribed proforma for permanent, semi-permanent assets acquired solely or mainly out of CHiPS/Policy grant;
4. The assets referred to in (3) above will be property of academic institution and shall remain so even post completion of the project. These academic institutions will comply to the following for said assets:
    4.1 During Project Period: for the purposes other than those for which the grant has been sanctioned.
    4.2 Post Project Completion: The academic institution will be free to use the assets for teaching and R&D purposes and the assets should not, without prior sanction of CHiPS, be disposed off or encumbered for a period of 3 years from the completion date of the project.
5. The academic institution shall send to the CHiPS at the end of each financial year as well as at the time of seeking further installments of the grant a list of assets referred to in (3) above; during the course of the project and for the year immediately after completion of the project within 2 months of completion of final year.
6. Should at any time academic institution cease to exist, such assets etc., shall revert to CHiPS;
7. The academic institution and industry shall jointly render progress-cum-achievement reports at interval of not exceeding six months on the progress made on all aspects of the project including expenditure incurred on various approved items during the period;
8. CHiPS or its nominee(s) will have the right of access to the books and accounts of the academic institution and industry for which a reasonable prior notice would be given;
9. The academic institution should maintain separate audited account for the project. If it is found expedient to keep a part or whole of the grant in a bank account earning interest, the interest, thus earned should be reported to this Department. The interest so earned will be treated as a credit to the institution to be adjusted towards future installments of the grant;

10. The Intellectual property and the rights associated with the project shall be agreed between the participating organizations before the start of the project. A copy of this agreement should be submitted along with the first progress–cum–achievement report to CHiPS. The Industry/ Industry Consortium/Institution(s) will make all efforts to protect intellectual property generated out of the project. The institution(s)/industry would submit periodic report to CHiPS for a period of minimum 5 years on the status of IPRs created/commercialization under the project. Furthermore, IPR must also reside in Chhattisgarh/India so that India has access and complete control to these rights in times of emergency to protect our national interest.
11. Application by academic institution for any other financial assistance or receipt of grant/loan from any other Agency/Ministry/Department for this project should have prior approval of CHiPS.
12. The academic institution(s) is not allowed to entrust the implementation of this project for which grant is received to another institution and to divert the grant received from CHiPS as assistance to the latter institution.
13. In case the industry/industry consortium is/are unable to continue with the project, the academic institution should send an intimation signed by all parties to CHiPS immediately. Further, the academic institution shall scout for a new contributing industry/industry consortium partner within 3 months of such an event. A letter of intimation along with due agreement of all parties will be submitted to CHiPS to showcase the new partnership. The duration of the project will be deemed extended by the period between date the of the letter intimating exit of first industry/industry consortium partner and date of letter intimating formation of new partnership.
14. In case of any delay in progress of the project, a one-time-only extension of 6 months may be sought jointly by all parties with relevant reasons sighted. The decision of the CEO, CHiPS will be binding on such extension. No escalation of project cost or increased demand for grant will be entertained on the basis of the extension.
15. Scope of the project may be enhanced/curtailed during the course of the project with due representation made to the PRSG. Any escalation of project cost or increased demand for grant or extension of timeframe of the project (not more than 6 months) will be approved by the CEO, CHiPS only upon recommendation(s) of PRSG, inclusive of all limitations referred above.
16. In case of any dispute on any matter, related to the project during the course of its implementation, the decision of the CEO, CHiPS, shall be final and binding on the proposal originating industry/ industry consortium and academic institute.

[A certificate of acceptance of Terms & Conditions, as above, has to be given by proposal originating industry and academic institution, as outlined below, while submitting the project proposal.]

1. We hereby accept the terms and conditions of grants, listed as above, for the project titled "....." submitted vide ref. no. ..... dated ..... to CHiPS for support.
2. The Chief Investigator at the Institute agrees to provide required support as detailed in the project proposal for successful implementation of the project.
3. Industry/ Industry Consortium agrees to provide required support as detailed in the project proposal for successful implementation of the project.

Sd/-
Signature of the Chief Coordinator
Proposal originating Industry/
Industry Consortium
along with Department,
Designation and Date

Sd/-
Signature of the Chief Investigator
(Academic Institution) along with
Department,
Designation and Date

Sd/-
Signature of the Head of the
Proposal originating Industry
along with Designation, Date and
Official Seal

Sd/-
Signature of the Head of the
Academic Institution along with
Designation, Date and Official
Seal

Proforma for Submitting R&D Project Proposal for Seeking Grant under Clause # 6.14, Support for Research and Development (R&D) of Electronics, IT & ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19

CHiPS, Government of Chhattisgarh

PART I - SALIENT INFORMATION

1.	Project Title	:						
2.	Project Objective	:						
3.	Brief project outline with specific technology aspects that are relevant	:						
4.	Project Duration	:	Month	Year	To	Month	Year	
				_		_		
5.	Proposed partners of the project							
	a. Industry/ Consortium	:	(Name)					
	b. Institution	:	(Name)					
	c. Others (Specify)	:	(Name)					
6.	Total Budget outlay along with contributions from:	:	Rs. (Details in Table 1 and 2)					
	a. Industry/ Consortium	:	Rs.					
	b. Institution	:	Rs.					
	c. CHiPS (Expected)	:	Rs.					
	d. Others (Specify)	:	Rs.					
7.	Expected output and outcome in physical terms	:						
8.	Major milestones with timelines	:		Item	Month	Year	Remark	
			M1					
			M2					
			M3					
9.	Objectively Verifiable Indicators for measuring the successful achievement of each of the milestones	:	Indicator 1					
			Indicator 2					
			Indicator 3					
10.	Need and Justification for the project covering: (*Feel free to attach any documentary evidence such as reports, studies, projections, etc.*)	:						

	a. Similar products/technologies currently available	:	
	b. Incremental/ significant innovation(s)/enhancement (s) planned in the project	:	
	c. Evidence to support commercial viability of the proposed development/ new product and Likely End User(s)	:	
11.	Industry Organization (*Attach separate sheet, if required. In case of consortium, attach separate information for each industry*)	:	
	a. Name	:	
	b. Year of Incorporation	:	
	c. Turnover [also indicate turnover in the proposed area of project]	:	
	d. Address	:	
	e. Legal status (MSME, Corporate Body, Industry Organization, Private Company with recognized R&D unit, etc.)	:	
	f. Core Business Area of the Industry/Consortium	:	
	g. List major Products manufactured by the Company	:	
	h. Justification for taking-up the present project	:	
	i. Availability of technical manpower to absorb the know-how generated	:	
	j. Availability of requisite infrastructure for in-house production of the project output(s)	:	
	k. Manufacturing tie-ups proposed, if any	:	
12.	Chief Coordinator Industry/ Consortium	:	
	a. Name & Designation	:	
	b. Department	:	

	c. Address	:	
	d. Telephone/ Fax/ e-Mail	:	
13.	Academic/ R&D Institution	:	
	a. Name	:	
	b. Address	:	
	c. Legal status (Academic Institution, Research Institution, Registered Society, etc.)	:	
14.	Chief Investigator	:	
	a. Name & Designation	:	
	b. Department	:	
	c. Address	:	
	d. Telephone/ Fax/ e-Mail	:	
	e. Qualifications to act as Chief Investigator of the project	:	
15.	Name and brief details of other organizations jointly participating in the project (including organization(s) abroad)	:	
16.	Steps taken to ensure successful product/ technology development and commercialization	:	

Disclaimer: - All details provided above are factual and true to the best of our knowledge.

Sd/-
Signature of the Chief Coordinator Proposal originating Industry/ Industry Consortium along with Department, Designation and Date

Sd/-
Signature of the Chief Investigator (Academic Institution) along with Department, Designation and Date

Sd/-
Signature of the Chief Investigator (Academic Institution) along with Department, Designation and Date

Sd/-
Signature of the Head of the Academic Institution along with Designation, Date and Official Seal

PART II - BACKGROUND INFORMATION

1.	Project Title	:		
2.	i. Chief Coordinator - Industry/ Consortium	:	Name	Designation
	ii. Chief Investigator - Institute	:	Name	Designation
	iii. Co-Investigator - Institute	:	Name	Designation
3.	Other Investigators of the Project with their Designations	:	Name	Designation
4.	Brief Bio-data of the Chief Coordinator - Industry/ Consortium (*Please attach separate sheets, if required*)	:		
5.	Brief Bio-data of the Chief Investigator and Co-Investigator(s) - Institute (including publications/ patents/ Industry interaction/ Technology transfer) (*Please attach separate sheets, if required*)	:		
6.	Other Commitments of the Chief Investigator and Co-Investigator(s) (including teaching, research, other responsibilities, association with other projects, etc.) (*Please attach documentary evidence as relevant*)	:		
7.	Indicate the percentage of time the Chief Investigator and Co-Investigator(s) would devote to the project (*Hours per week*)	:		
8.	Details of work done in related areas, including the ongoing/ completed projects (last three), by the Chief Investigator/ Co-Investigator(s)/ R&D Team (*In progress/ Successfully completed on schedule/ abandoned.*)	:		
8.1	i. Project Title	:		
	ii. Funding Agency	:		

	iii. Brief Project Summary	:	
	iv. Technical Status vis-a-vis objectives	:	
	v. Financial Status (Total Project outlay, expenditure to date)	:	
	vi. Duration and year of initiation	:	
	vii. Industry interaction/ know-how transferred	:	
	viii. Status	:	
8.2	i. Project Title	:	
	ii. Funding Agency	:	
	iii. Brief Project Summary	:	
	iv. Technical Status vis-a-vis objectives	:	
	v. Financial Status (Total Project outlay, expenditure to date)	:	
	vi. Duration and year of initiation	:	
	vii. Industry interaction/ know-how transferred	:	
	viii. Status	:	
8.3	i. Project Title	:	
	ii. Funding Agency	:	
	iii. Brief Project Summary	:	
	iv. Technical Status vis-a-vis objectives	:	
	v. Financial Status (Total Project outlay, expenditure to date)	:	
	vi. Duration and year of initiation	:	
	vii. Industry interaction/ know-how transferred	:	
	viii. Status	:	
9	Brief summary of other project proposals (submitted by any of the Investigators) awaiting consideration of CHiPS and/or other funding agencies such as DST, DSIR, DRDO, MHRD, etc.	:	
10.	Infrastructure and other facilities available at the	:	

	industry organization initiating this project:		
	i. List of major equipment	:	
	ii. Existing manpower and other personnel, with names, available for the project on full-time basis	:	
	iii. Facilities for production, commercialization and marketing	:	
11.	Infrastructure and other facilities available at the institute for undertaking this project:	:	
	i. List of major equipment	:	
	ii. Existing manpower and other personnel, with names, available for the project on full-time basis	:	

Additional Information Required:

1. About the Industry(s): A brief write-up covering:
   i. Brief history of the prospective company(ies) including core competency areas, products being manufactured, collaborators, etc. may be provided [including recent annual reports (three years) and company brochure];
   ii. Whether the industry/participating industry member(s) of industry consortium is(are) recognized by DSIR for the in-house R&D /STPI registered units/Export oriented units (EOU) registered with Ministry of Commerce/Technology startups (in existence of minimum two years). Please provide the supporting documents for the same.
   iii. Please indicate the size of the in-house R&D set-up and its recent achievements in development of products/ processes/ technology, patent taken, etc.;
   iv. Any other information in support of the proposal.

2. About the Industry(s): A brief write-up covering:
   i. Research Strengths, linkages with industry;
   ii. A brief write-up on major R&D projects, up to five, taken-up by the institute;
   iii. IPRs filed/ obtained; and
   iv. Any other information in support of the proposal.

****

PART III - TECHNICAL INFORMATION

1.	Aim and Scope of the project (in terms of specific physical achievements)	:	
2.	Detailed description of the Project (including specifications to be attained, etc.)	:	
3.	Summary of similar work being done elsewhere in the country	:	
4.	Detailed PERT/ BAR Chart with intermediate milestones (*Attach Separate Sheet*)	:	
5.	List the personnel already working in the industry organization(s) and Institute who would be transferred to work full time on this project	:	
6.	Additional Manpower required and estimated time frame to position the same	:	
7.	i. Specific problems, hold-ups and difficulties foreseen in the implementation of the project	:	
	ii. How does Chief Investigator/ Chief Coordinator propose to overcome them?	:	
8.	Details of possible alternative arrangements, if the Chief Investigator leaves institution or is unable for any other reason to continue on this project	:	

PART IV - RESOURCE REQUIREMENTS

Table 1: Budget Requirements (Rs. In Lakhs)

Head	**Industry Support***	**CHiPS Support**	**Others (Specify)**	**Total**
Capital Expenditure				
Consumable stores				
Manpower				
Operating Expenses				
Contingencies	-	-	-	
Registration and Licensing Fees (if any)				
Overheads, if any				
Other expenses, not covered above				
Total	-	-	-	

* If being provided by more than one entity, contribution to be made by each entity should be shown separately.

Table 2: Budget Requirements (Year-Wise) (Rs. In Lakhs)

Head	**1st Year**				**2nd Year (s).....**			
	Industry Support*	CHiPS Support	Others (Specify)	Total	Industry Support*	CHiPS Support	Others (Specify)	Total
Capital Equipment								
Consumable stores								
Manpower								
Operating Expenses								
Contingencies	-	-	-	-	-	-	-	
Registration and Licensing Fees (if any)								
Overheads, if any								

Other expenses, not covered above								
Total	–	–	–	–	–	–	–	

* If being provided by more than one entity, contribution to be made by each entity should be shown separately.

Table 3: Budget Requirements - Capital Equipment (Rs. In Lakhs)

S. No.	Item Description	Specifications	Cost
1.	–	–	
2.	–	–	
3.	–	–	
...	–	–	

Table 4: Manpower Details (Rs. In Lakhs)

S. No.	Designation	Monthly Salary	1st Year		2nd Year		Total
			No. of Posts (*)	Total Salary (**)	(*)	(**)	(**)
1.	–	–	–	–	–	–	
2.	–	–	–	–	–	–	
3.							
...							
	Total						

PART V - ENDORSEMENT BY THE HEADS OF THE INDUSTRY/ INDUSTRY CONSORTIUM AND INSTITUTION

1. We hereby submit the project proposal titled "..... ...." for consideration of the Chhattigarh Infotech Promotion Society, Government of Chhattisgarh.
2. We agree to abide by the terms & conditions governing the subsidy disbursement.
3. In case the project is approved, we undertake to:
   i. make available facilities to carry it out, and agree to provide requisite support for the successful completion of the project.
   ii. arrange for the submission of periodic progress reports and other information that may be required by the Chhattigarh Infotech Promotion Society and in general to ensure that the conditions attached to the award of such subsidy are fulfilled by our institution/organization(s).
4. We certify that in case present chief coordinator/ investigator is not available for any reason to continue work on this project, the following persons will be available to carry it through to completion:

S. No.	Name	Designation
1.	_	
2.	_	

5. The Industry/ Industry Consortium and Institution(s) have reached a formal agreement on distribution of responsibilities, IPR sharing, sharing of royalty/lump sum, and know-how transfer mechanism from the institute to the Industry/ Industry Consortium. A copy of the same is enclosed.
6. We certify that the i) Industry/ Consortium and Institution do not have common Director(s)/Trustee(s); and ii) the Project Chief Coordinator (Industry/ Consortium) and Chief Investigator (Institute) are not related to any of the Director(s)/ Trustee(s) of the Industry/ Consortium and Institution.
7. We certify that we are the competent authority, by the virtue of the administrative and financial powers vested in us by .... and .... to undertake the above stated commitments on behalf of our institution/ organization(s).
8. The information provided is correct

Sd/-
Signature of the Chief Industry Coordinator,
Designation and Date

Sd/-
Signature of the Chief Investigator
Designation and Date

Sd/-
Signature and Official Seal of the Organization/ Consortium / Head of the Institution
Designation
Date:

Sd/-
Signature and Official Seal of the Head of the Industry
Designation Date:

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.